श्री गोविन्दराम मिरी: उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी को पेड़ लगाने चाहिये।

उपसभापति: प्रधान मंत्री को ही क्यों, हम सबको पेड़ लगाने चाहिये। एक आदमी को नहीं बल्कि सबको लगाने चाहिये।

RE. DEMONSTRATION BEFORE PARLIAMENT BY ALL INDIA GRAMIN BANK EMPLOYEES AGAINST DISCRIMINATION AND DISPARITY IN WAGE STRUCTURE AND SERVICE CONDITIONS

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): पीठासीन हुए

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): महोदय, मैं सदन में आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्ज एसोसिएशन और आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के लोग जो दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी प्रमुख मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उनकी प्रमुख मांग यह है कि देश के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाये साथ ही बैंकिंग से छठे वेतन समझौते को ग्रामीण बैंकों में भी लागू किया जाये। इन मांगों को लेकर ये दो संगठन आज दिल्ली में धरना दे रहे हैं। सवाल यह है कि ग्रामीण बैंकों को भी मजबूत किया जाना चाहिये। क्या हमारी सरकार सार्वजनिक षेत्र के अंदर जो बैंक हैं उन बैंकों को निजी क्षेत्र में देने का इरादा रखती है? इसी वजह से इनकी जो उदारीकरण की नीति है इस नीति के तहत ग्रामीण निजी क्षेत्र में लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि वे ग्रामीण बैंक गांवों में गरीबों को, गरीब किसानों को, खेतीहर मजदूरों को कर्जा मुहैया करने मे मदद करते हैं। और इनके माध्यम से सरकार जो गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं चला रही है उसके तहत उनको मदद मिलती है। यदि मान लिया जाये कि इन बैंकों मे कुछ कमजोरियां हैं तो उनको दूर कर इसे मजबूत बनाया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाये तो वित्त मंत्रालय और हमारी सरकार ने जो लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है उससे इस बात की मंशा जाहिर होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे बैंक हैं उनको निजी क्षेत्र में ले जाना चाहती है। यही दो प्रमुख मांगे हैं जिनकी चर्चा मैंने सदन में की। इनकी मांग है कि सभी ग्रामीण बैंकों को और क्षेत्रीय बैकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये। मैं समझता हूं कि सदन की इस मामलें पर सहमति होगी और इनकी बैंकिंग प्रणाली को मजबूती मिलेगी। साथ ही बैंकिंग उद्योग में जो छठा वेतन समझौता हुआ था उसको वित्त मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन में हुई विसंगतियां दूर नहीं हो पा रही हैं। पेंशन की स्कीम में उनको जो मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। कम्प्यूटर के एलाउन्सेज जो दूसरे डिपार्टमेंट में मिलते हैं वे भी उनको नहीं मिलते हैं। इस तरह से डिस्पेरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इससे सरकार दोहरी नीति पर बैंकों को ले जाना चाहती है। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण बैंकों में जो बैंकों का छठा वेतन समझौता हुआ था उसको लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय आवश्यक कदम उठाये ताकि उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†श्री जलालुद्दीन अंसारी "बिहार": महोदय - मैं सदन में आल इंडिया ग्रामीण वर्कर्स एसोसिएशन और आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के लोग जो दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं उनकी प्रमुख मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उनकी प्रमुख मांग यह है कि देश के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाये साथ ही बैंकिंग से छठे वेतन समझौते को ग्रामीण बैंकों में भी लागू किया जाये। इन मांगों को लेकर ये दो संगठन आज दिल्ली में धरना दे रहे हैं। सवाल यह है कि ग्रामीण बैंकों को भी मजबूत किया जाना चाहिये। क्या हमारी सरकार सार्वजनिक षेत्र के अंदर जो बैंक हैं उन बैंकों को निजी क्षेत्र में देने का इरादा रखती है? इसी वजह से इनकी जो उदारीकरण की नीति है इस नीति के तहत ग्रामीण निजी क्षेत्र में लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि वे ग्रामीण बैंक गांवों में गरीबों को, गरीब किसानों को, खेतीहर मजदूरों को कर्जा मुहैया करने मे मदद करते हैं। और इनके माध्यम से सरकार जो गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं चला रही है उसके तहत उनको मदद मिलती है। यदि मान लिया जाये कि इन बैंकों मे कुछ कमजोरियां हैं तो उनको दूर कर इसे मजबूत बनाया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाये तो वित्त मंत्रालय और हमारी सरकार ने जो लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है उससे इस बात की मंशा जाहिर होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे बैंक हैं उनको निजी क्षेत्र में ले जाना चाहती है। यही दो प्रमुख मांगे हैं जिनकी चर्चा मैंने सदन में की। इनकी मांग है कि सभी ग्रामीण बैंकों को और क्षेत्रीय बैकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये। मैं समझता हूं कि सदन की इस मामलें पर सहमति होगी और इनकी बैंकिंग प्रणाली को मजबूती मिलेगी। साथ ही बैंकिंग उद्योग में जो छठा वेतन समझौता हुआ था उसको वित्त मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन में हुई विसंगतियां दूर नहीं हो पा रही हैं। पेंशन की स्कीम में उनको जो मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। कम्प्यूटर के एलाउन्सेज जो दूसरे डिपार्टमेंट में मिलते हैं वे भी उनको नहीं मिलते हैं। इस तरह से डिस्पेरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इससे सरकार दोहरी नीति पर बैंकों को ले जाना चाहती है। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण बैंकों में जो बैंकों का छठा वेतन समझौता हुआ था उसको लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय आवश्यक कदम उठाये ताकि उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†Transliteration in Arabic Script

اسی وجہ سے ان کی جو اور سیکشن کی نیتی ہے اس نیتی کے تحت گرامین بنک شیتر میں لوکل ایریا بینک کھولنے کا اعلان کیا ہے - ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گرامین بینک گاؤں میں غریبوں کو - غریب کسانوں کو - کھیتی پر مزدوروں کو قرضہ مہیا کرنے میں مدد کرنے میں مدد کرتے ہیں - اور انکے مادھیم سے سرکار جو غریبوں کی بھلائی کیلئے یوجنائیں چل رہی ہیں اس کے تحت انکو مدد ملتی ہے - یدی مان لیا جائے کہ ان بینکوں میں کچھ کمزوریاں ہیں تو انکو دور کر اسے مضبوط بنایا جانا چاہیئے - یدی ایسا نہ کیا جائے تو وت منترالیہ اور ہماری سرکار نے جو لوکل ایریا بینک کھولنے کا اعلان کیا ہے - اس سے اس بات کی منشا ظاہر ہوتی ہے - کہ سارو جنک شیتر میں جو ہمارے بینک ہیں انکو نجی شیتر میں لے جانا چاہتی ہے - یہی دو ہر ملکو مانگیں ہیں - جنکی چرچا میں نے سدن میں کی ہے - انکی مانگ ہے کہ سبھی گرامین بینکوں کو اور شیتری بینکوں کو ملا کر علاقیہ گرامین بینک کی استھاپنا کی جائے - میں سمجھتا ہوں کہ سدن کی اس معاملے پر سہمتی ہوگی اور انکی بینکنگ پرنالی کو مضبوطی ملیگی ساتھ ہی بینکنگ اوپریشن میں جو چھٹا ویتن سمجھوتہ ہوا تھا اسکو وت منترالیہ کی طرف سے کارنوٹ کیا جا رہا ہے جسکے کارن گرامین بینکوں کے کرمچاریوں اور پرادھیکاریوں کے ویتن میں ہوئی وسنگتیاں دور نہیں ہو پا رہی ہیں - پینشن کی اسکیم میں انکو جو ملنا چاہیئے تھا وہ نہیں مل پا رہا ہے - کمپیوٹر کے اللاؤنسز جو دوسرے بنکوں میں ملتے ہیں وہ بھی انکو نہیں ملتے ہیں - اسطرح سے ڈیسپیریٹی ہے ڈسکریمینیشن ہے - اور اس سے سرکار بینکوں کو دوسری نیتی پر لے جانا چاہتی ہے - اس لئے میں سدن کے مادھیم سے - آپکے مادھیم سے وت منتری مہودے سے کہنا چاہونگا کہ گرامین بینکوں میں جو بینکو کا چھٹا ویتن سمجھوتہ ہوا تھا - اسکو لاگو کرنے کیلئے وت منترالیہ آوشیک قدم اٹھائے تاکہ انکی جو مانگ ہے اسکو پورا کیا جا سکے - انھیں شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں - "ختم شد"

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जलालुदीन जी से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं इस सदन के सामने यह मांग रखना चाहूंगी कि ग्रामीण बैंकों को शहरों का जो पुअर कज़न माना जा रहा है, यह उचित नहीं है। भारत की उन्नति मुख्यतः ग्रामों की उन्नति पर निर्भर करती है। जो यह आंदोलन शुरू हुआ है, वे संसद तक मार्च कर रहे हैं और दूसरी यूनियनें जो आल इंडिया रूरल बैंक्स एसोसियेशन है, उसके कर्मचारी भी कुछ दिनों के बाद आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उनकी

भी यही मांग है। मैं उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि उनके लिए, जो सुविधायें अन्य स्पांसर बैंकों को मिल रही हैं, वह उनको भी मिलें और सिक्सथ बाइपार्टाइट वेज सेटलमेंट को लागू करने की व्यवस्था की जाए और प्राइस इंडेक्स लिंक्ट पेंशन स्कीम लागू की जाए। साथ ही उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए नये वेतनमान जल्दी से जल्दी लागू किए जाएं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी आज फिर से सदन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। साढ़े तीन साल पहले भी ये लोग यहां आए थे और उन्होंने धरना दिया था। उस समय जब लोकसभा में इस पर सवाल उठाए गए तो कई प्रमुख लोगों ने, जो आज सरकार में हैं या सरकार का सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया था। मैं नाम गिनाना नहीं चाहता, श्री चटर्जी, श्री श्रीकांत जेना और श्री चाकू, और भी कई बड़े-बड़े नेता थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नेशनल रूरल बैंक in rural areas can advance beyond 40 per cent and would be a source of profit compared to the other commercial banks. Let them come forward with a Bill for establishing this National Rural Bank of India. आज सरकार में यह लोग मौजूद हैं। आज दुबारा फिर से ग्रामीण बैंक के सारे लोग यहां पर हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से आज यह घोषणा हो कि वह नेशनल रूरल बैंक्स के बारे में कब यहां बिल लाना चाहती है। अफसोस की बात है कि इसको पीछे डालकर लोकल बनाने की स्कीम घोषित की गई है। अब लोकल एरिया बैंक एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का पैसा निकालकर शहरी क्षेत्रों में लें जाकर जमा कर देंगे या वहां लगा देंगे। मैं समझता हूं कि इस लोकल एरिया बैंकों की स्कीम को खत्म कर देना चाहिए, अगर हम वास्तव में नेशनल रूरल बैंक आफ इंडिया को एस्टेबिलश करने के पक्ष में हैं।

दूसरी बात मेरी यह है कि 14 फरवरी, 1995 को बैंकिंग उद्योग ने छठा वेतन समझौता किया था। परन्तु ग्रामीण बैंकों में इसको लागू नहीं किया गया। तर्क दिया गया कि वहां घाटा हो रहा है। मैं सरकार के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि सार्वजनिक बैंक भी घाटे में चल रहे हैं। अगर उनके इम्पलाईज पर छठा वेतन आयोग का समझता लागू हो गया है तो ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर यह लागू क्यों नहीं किया गया? मैं चाहता हूं कि सरकार इ प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को भी छठे वेतन समझौते के अनुसार तनख्वाह और सुविधायें प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा अभी माननीय भंडारी जी ने उठाया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के व्यवस्था इतनी खराब है कि उसके जो कृषि इतर क्षेत्र हैं, उनके साथ ऋण देने में जो व्यवहार किया जाता है, बैंकों द्वारा, सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा जमीन आसमान का अतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी प्रक्रियायें भी इतनी जटिल हैं कि उसका बहुत विस्तृत विवरण है, उसके लिए ज्यादा समय चाहिये, इसलिए मैं आपका ज्यादा खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। पिछली सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में सारी बैंकिंग प्रणाली ने जितना ऋण विकास के लिए दिया, उसका केवल 13 या 14 प्रतिशत गांवों में दिया गया। अगर आप उनकी सी०डी० रेश्यों देखें, जितना जमा होता है, जितना उसके बाद ऋण दिया जाता है, जितनी भी बैंकों की ग्रामीण शाखायें हैं, उनकी सी०डी० रेश्यों खराब है और शहरों में और कृषि इतर क्षेत्रों में बहुत अच्छा है। कहीं कहीं तो यह 100 प्रतिशत के ऊपर 117, 137 प्रतिशत तक है। जमा राशि गांवों की ब्रांचें ज्यादा ले आती हैं और कर्ज उनके कम दिया जाता है। रिज़र्व बैंक ने उनके लिए केवल 18 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था। ऐसा कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, एकाध को छोड़ कर, जिसने 18 प्रतिशत का लक्ष्य कभी किसी एक बिन्दु के ऊपर प्राप्त किया हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण व्यवस्था को बिलकुल सुधरा और सुथरा रुप देने के लिए इन ग्रामीण बैंकों का एक अलग ढांचा बनाए जाने की जो बात भंडारी जी ने कही है, उनकों क्रियान्वित करने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए। धन्यवाद।

REÄ REPORTED STATEMENT BY COMMERCE SECRETARY, CONFIRMING INDIA'S DECISION TO UP-GRADE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN ACCORDANCE WITH WORLD STANDARDS

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal) : Sir, while our Minister of Commerce is doing a commendable job in Singapore, at this moment, defending our position against the western governments' pressure to bring in labour standards, investment policies and all that, which we welcome, I find that from his department, certain other policies are enanating which are not in conformity with the position which this particular House has taken in the past or with the decisions declared by the Government in the past or even in terms of the Common Minimum Programme. I have nothing to say against a civil servant. I am assuming that the civil servant is speaking on behalf of the Government and is enunciating its policies. Shri Tejendra Khanna who is the Commerce Secretary has recently come out with a number of statements. I am opposed to both the substance and the language used. For exam-